International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232
Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 4; Issue 5; September 2018; Page No. 42-43

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय एक अध्ययन

विपिन कुमार सिंह
शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

वर्तमान परिदृश्य के सम्बन्ध में देखा जाय तो संघीय सरकारों में सार्वजनिक व्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है एवं समाज में फैली हुई आर्थिक विषमता को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि सार्वजनिक व्यय को 1920 तक अर्थशास्त्रीयों एवं बौद्धिक वर्गो द्वारा उपेक्षित किया जाता रहा। एडम स्मिथ एवं अन्य अनेक क्लासिक अर्थशास्त्रीयों द्वारा इसे अनावश्यक एवं गैरजरूरी माना जाता रहा है। एडम स्मिथ (1776) ने सरकार के कार्यो के बारे में बताते हुये लिखा कि सरकार को अपने कार्यो को ''न्याय पुलिस एवं सेना तक ही सीमित रखना चाए'' Zahir, 1972, ऐसे ही अन्य अनके अर्थशास्त्रीयों ने भी सार्वजनिक व्यय को मूर्खतापूर्ण व्यय की संज्ञा दी।

हालांकि कीन्स, टेलर (1953), मुसग्रेव आदि अर्थशास्त्रीयों ने सार्वजनिक व्यय को आवश्यक कदम बताया।

सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित करती है। ऐसे में आज सम्पूर्ण विश्व में सार्वजनिक व्यय काफी तीव्र गति से बढ़ा हुआ है। इस कारण आधुनिक अर्थशास्त्री इसका विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का वृहद अध्ययन करते हैं। इस सम्बन्ध में कीन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भारत जैसे विकासशील देश में सार्वजनिक व्यय न केवल आर्थिक स्थायित्व का एक साधन है वरन् अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ रोजगार वृद्धि में भी कारगत सिद्ध होता है। जैसा कि मनरेगा जैसी बड़ी योजनाओं में हमें देखने को मिलता है साथ ही साथ यह लोगो को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालने व असमानता कम करने का एक बहुत ही कारगर अस्त्र साबित हो रहा है। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, विधवा, वृद्धा पेंशन योजना सहित अन्य अनेक योजनायें जिससे कि सामाजिक विषमता कम करने के साथ–साथ लोगो के जीवनयापन के स्तर में सुधार लाया जा सके।

इस प्रकार सरकारें जहां एक तरफ देश के नागरिको को विभिन्न सामाजिक योजनायें देकर उन्हे सशक्त बना रही है। वहीं दूसरी तरफ रियाती दरों पर खाद्य सामान भी उपलब्ध करवा रही है।

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम

1. रोजगार परक कार्यक्रमः– रोजगार परक कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अनको योजनाएं संचालित कर रही है जैसे– ग्रामीण रोगार गारण्टी योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना, स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों युवा व्यावसायिक तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता योजना।
2. आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम– इसके अन्तर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं इन्दिरा आवास योजना, भारत निर्माण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण जलापूर्ति योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।

इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। यह बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी एवं विकलांगता की स्थिति में नागरिको को सरकारी सहायता प्रदान करता है।

इसके अन्तर्गत पांच योजनाएं शामिल हैं

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
5. अन्नपूर्णा योजना

इसे अलावा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 से मोदी के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण के लिए शुरू की गयी कुछ प्रमुख सरकारी योजनायें

1. प्रधानमंत्री जनधन योजना
2. प्रधानमंत्री आवास योजना
3. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना
4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
5. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
6. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
7. अटल पेंशन योजना
8. आयश्मान भारत योजना
9. सांसद आदर्श ग्राम योजना
10. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
11. राष्ट्रीय पोषण मिशन
12. प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
13. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
14. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना
15. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
16. प्राइम मिनिस्टर एम्लाइमेंट जनरेशन प्रोग्राम
17. प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना
18. आपरेश ग्रीन मिशन

इत्यादि प्रमुख सामाजिक सेवायें भी सरकार द्वारा संचालित हो रही हैं।

इसी प्रकार अन्य अनेक प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम (मनरेगा), व्यावसायिक प्रशिक्षण (एसजीएलवाई), स्वास्थ्य, आवास एवं विकास

सम्बन्धी अनके कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी रोजगार तथा कुशल मजदूरी के अवसर उपलब्ध करवाना है जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक उन्ययन हो सके।

सन्दर्भ

1. रीता माथूर, लोक वित्त– पेज नं0 120–122
2. जे0पी0 मिश्रा, लोक वित्त– पेज नं0 110–112
3. समसामयिक घटना चक्र (नितियां, योजनायें एवं कार्यक्रम)– पेज नं0 23–31
4. India.gov.in